सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रतन लाल

विरूद्ध

पंजाब सरकार

(के. सुब्बा राव, के. सी. दास गुप्ता और रघुबर दयाल, जे. जे)

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958। 611 - आपराधिक कानून -मुक़दमे में आने से पहले निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना अधिनियम का बल- क्या उच्च न्यायालय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? के तहत न्यायालय पर गुड़गांव जिले के पलवल के निवासी अपीलार्थी ने घर में अतिक्रमण किया और 7 साल की लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। 31 मई, 1962 के एक आदेश द्वारा, उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसे जुर्माना भरने हेतु दोषसिद्ध किया गया था। दोषी ठहराए जाने के समय वह 16 वर्ष का था।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का विस्तार किया गया था 1 सितंबर, 1962 को गुड़गांव और इसलिए उसकी दोषसिद्धी के समय मजिस्ट्रेट

के पास अधिनियम के तहत कोई आदेश देने की कोई शक्ति या कर्तव्य नहीं था। अपीलार्थी की अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा 22 सितंबर, 1962 के उनके आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उनकी पुनरीक्षण याचिका को भी उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर, 1962 को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आधार नहीं लिया गया कि इस मामले में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद, अपीलार्थी ने एक आपराधिक विविध याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय से एस के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया। 11 अधिनियम और एस. एस. के तहत आदेश पारित करना। 3 , 4 या अधिनियम की धारा 6 के तहत भी हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और लिए गए आधारों में से एक यह था कि उच्च न्यायालय को धारा 11 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। तथा धारा 3,4,6 के तहत आदेश पारित करना चाहता था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र अस्वीकार

किए जाने के बाद, अपीलार्थी विशेष अनुमति से इस न्यायालय में आया। अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित (पर सुब्बा राव और दास गुप्ता, जे. जे.): उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाए कि वह एस 6 के तहत आदेश करे या यदि वह ऐसा करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को प्रति प्रेषित करे। यह सच है कि सामान्यतः यह अदालत अनिच्छुक होती है कि किसी पक्ष को उसके समक्ष पहली बार कोई मुद्दा उठाने की अनुमति दे।, लेकिन इस मामले में दोनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी की। यह सच है कि अपीलार्थी ने पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक अधिनियम के प्रावधानों को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया, लेकिन यह न्यायालय को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करता है।

अपील में अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय, एस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत, एक आदेश दें। 6 (1) .

यह अधिनियम दंडशास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक ऐतिहासिक कदम है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने से अधिक सुधार करना है। यह अधिनियम 21 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों और उससे अधिक उम्र के अपराधियों और ऐसे अपराधियों को अलग करता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और अपराध करने के दोषी हैं और जो कम अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के मामले में, उन्हें चेतावनी देने के बाद या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए अदालत को पूर्ण विवेकाधिकार दिया जाता है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में उन्हें कारावास की सजा नहीं देने के लिए अदालत को एक निषेधाज्ञा जारी की जाती है, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधियों के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के तहत व्यवहार करना वाछनीय नही है।

अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है अपराधी पर मुकदमा चलाने और उसे कारावास की सजा देने का

अधिकार और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी जब मामला अपील या पुनरीक्षण पर उसके समक्ष आता है। उप-धारा केवल उस मामले में जहां निचली अदालत है, अधिनियम के तहत आदेश देने के लिए अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। वह आदेश दिया जा सकता था। उसमें प्रयुक्त वाक्यांश काफी व्यापक है जो अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय को, जब मामला सामने आता है, तो ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाता है। इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से व्यापक बनाया गया था क्योंकि यह अधिनियम एक सामाजिक सुधार को लागू करने के लिए बनाया गया था। चूँकि अधिनियम कारावास की अवधि को नहीं बदलता है, बल्कि केवल अपराधी को सुधारने का प्रावधान करता है, वहाँ यह कोई कारण नहीं है कि विधायिका को इस तरह की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए था, भले ही मामला अभियुक्त के खिलाफ किसी न किसी स्तर पर न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम में लंबित था।

एस 6 (1) में "अदालत" शब्द में अपीलीय न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय भी शामिल है।

श्री रघुबर दयाल, जे. (असहमति जताते हुए) जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया जिसके लिए एस. एस. 3 और

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा एसजेजे तथा के प्रावधान लागू हो सकते है, और ऐसा निष्कर्ष, चाहे वह विचारण न्यायालय का हो या अपीलीय न्यायालय का, अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दिया जा सकता है। अपील या पुनरीक्षण न्यायालय अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता जब मामला अपील या संशोधन में उसके समक्ष आता है।

यह सच है कि अपीलीय अदालतों ने पक्षों को अनुमति दी है। मामले के लंबित रहने के दौरान अधिनियमित कानून का लाभ, लेकिन यह तब किया जाता है जब पक्षकार मामले को देखते हुए आगे मुकदमा कर सकते हैं। कानून को बदल दिया और कार्यवाही की बाहुल्यता को बचाने के लिए किया जाता है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

रामजी मिसर बनाम बिहार राज्य, [1963] पूरक। 2 एस. सी. और. 745 संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 1962 का 190। 1962 के आपराधिक संशोधन संख्या 1172 में पंजाब उच्च न्यायालय के 27 सितंबर, 1962 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

नानक चंद, अपीलार्थी ।

गोपाल सिंह, और. एन. सचथे और और. एच. ढेबर उत्तरदाता।

10 अप्रैल, 1964। श्री सुब्बा राव और दासगुप्ता का निर्णय जे.जे. सुब्बा राव जे. रघुबर दयाल द्वारा दिया गया था, जे. ने असहमतिपूर्ण राय दी।

सुब्बा राव, जे. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील एक अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाती है कि वह अपने एस 6 के तहत। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 20), जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है, उस अभियुक्त के संबंध में जिसे अधिनियम लागू होने से पहले निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था कि शक्ति प्राप्त है या नहीं।

तथ्य अब विवाद में नहीं हैं। गुड़गांव जिले के पलवल के निवासी अपीलार्थी ने घर में अतिक्रमण किया और 7 साल की लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पलवल के समक्ष विचारण के लिए भेजा गया था। उक्त मजिस्ट्रेट ने 31 मई, 1962 को उन्हें एस. एस. के तहत दोषसिद्ध किया 451 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उन्हें प्रत्येक गणना के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और निर्देश दिया कि सजाएं साथ-साथ चलनी चाहिए। उन्होंने आगे जुर्माना लगाया। दोषी से रु. 200 / - एस 451 के तहत

अपीलार्थी पर। 451 भारतीय दंड संहिता और आदेश दिया कि, जुर्माने के भुगतान के चूक में। उसे दो महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरना चाहिए। दोषी ठहराए जाने के समय अपील करने वाले की आयु 16 वर्ष थी। इस अधिनियम को 1 सितंबर, 1962 को गुड़गांव जिले तक विस्तारित किया गया था और इसके अलावा, जब अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किया गया था, तब मजिस्ट्रेट के पास अधिनियम के तहत कोई आदेश देने की कोई शक्ति या कर्तव्य नहीं था। अपीलार्थी ने अपने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की, जिन्होंने 22 सितंबर, 1962 के अपने निर्णय से अपील को खारिज कर दिया। हालाँकि जब तक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील की, तब तक उक्त अधिनियम लागू हो चुका था, न तो अपीलार्थी ने अधिनियम के प्रावधानों पर विश्वास किया और न ही विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इसके तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर संशोधन को 27 सितंबर, 1962 को खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था, लेकिन पुनरीक्षण याचिका में कोई आधार नहीं लिया गया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को एस के तहत कार्य करना चाहिए था। अधिनियम की धारा 1

में पुनरीक्षण याचिका दायर किए जाने के बाद। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने 1962 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 793 दायर की जिसमें उच्च न्यायालय से अनु. सं. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था। 11 अधिनियम और एस. एस. के अधीन आदेश पारित करना। 3 , 4 या उनमें से 6 उक्त आवेदन भी छूट गया था। दुर्भाग्य से उक्त आवेदन रिकॉर्ड में नहीं है और हम आवेदन में मांगी गई राहत के सटीक दायरे और उन कारणों को जानने की स्थिति में नहीं हैं जिनके लिए इसे खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने कला के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 134 (1) (सी) इस न्यायालय में अपील करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र के लिए संविधान की धारा। माँगने के कारणों में से एक ऐसा प्रमाण पत्र था कि उच्च न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए अधिनियम की धारा 3,4 या 6 तथा 11 के तहत आदेश पारित किए। उस याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति प्राप्त करके इस न्यायालय में वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि, मामले में स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को को अधिनियम की धारा 11 के

तहत कार्य किया है। अधिनियम और अपीलार्थी को जारी किया गया। उसे जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण का परीक्षण करना चाहा था। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं है और इसलिए, यह परीवीक्षा पर छोडना चाहा होगा अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वह अधिनियम के लागू होने से पूर्व पहले दोषी ठहराया गया था आगे वह तर्क देता है कि न तो एस. 11 न ही अधिनियम का। 6 के आधार पर उसमें प्रयुक्त वाक्यांश विज्ञान, परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है वर्तमान मामले में। किसी भी दृष्टिकोण से, वह कहता है कि अपीलार्थी, नहीं पुनरीक्षण याचिका खारिज होने तक इस याचिका को उठाया उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत, उठाने के लिए अपने डिफ़ॉल्ट से वर्जित है इस बहुत देर से चरण में यह विवाद।

यह अधिनियम आधुनिक स्वतंत्रता की प्रगति में ऐतिहासिक कदम है। दंडविज्ञान के क्षेत्र में सुधार की तीव्र प्रवृत्ति। इसका परिणाम यह है कि इस सिद्धांत की मान्यता कि आपराधिक कानून का उद्देश्य यह व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने से अधिक सुधार करने के लिए है। मोटे तौर पर कहा जाए तो यह अधिनियम 21 साल से कम उम्र के अपराधियों को अलग करता है। उम्र और उस उम्र से ऊपर के लोग, और अपराधी जो दोषी हैं मृत्युदंड या

आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और जो कम अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के मामले में अदालत को उन्हें रिहा करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है। अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तें, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में एक निषेधाज्ञा न्यायालय को उन्हें कारावास की सजा न देने के लिए जारी किया जाता है, बशर्ते कि यह संतुष्ट न हो कि अपराध की प्रकृति और अपराधियों के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ अधिनियम की धारा 3 और 4 अधिनियम के तहत व्यवहार करना वांछनीय नहीं है।

इस छोटी सी पृष्ठभूमि के साथ अब हम अधिनियम के प्रावधान प्रासंगिक पढ़ेंगे ।

धारा 6. (1) जब कोई व्यक्ति बीस-एक वर्ष से कम आयु का हो उम्र का अपराध करने का दोषी पाया जाता है। कारावास से दंडनीय अपराध (लेकिन आजीवन कारावास के साथ नहीं), वह न्यायालय जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति पाया जाता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि, अपराध की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियाँ अपराध और अपराधी का चरित्र, यह धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार

करना वांछनीय नहीं होगा, और यदि न्यायालय किसी सजा को पारित करता है अपराधी पर कारावास की सजा, यह होगा ऐसा करने के अपने कारणों का पता लगाएँ।

(2) स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से क्या यह होगा धारा 3 या धारा 4 के तहत व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराधी के साथ न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट, यदि कोई हो, और किसी अन्य पर विचार करें। चरित्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।और अपराधी की शारीरिक और मानसिक स्थिति।

अधिनियम की धारा 11 (1) कुछ भी निहित होने के बावजूद संहिता या कोई अन्य कानून, इस अधिनियम के तहत एक आदेश प्रयास करने के लिए सशक्त किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और अपराधी को कारावास की सजा और इसके द्वारा भी उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जब मामला हो अपील या पुनरीक्षण पर उसके समक्ष आता है।

(2) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहाँ धारा 3 या धारा 4 के तहत आदेश दिया जाता है। अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा (उच्च न्यायालय के अलावा), एक अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें अपील आमतौर पर पूर्व अदालत से दोषसिद्ध होते हैं।

(3) किसी भी मामले में जहां 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वर्ष की आयु को अपराध करने का दोषी पाया गया है। अपराध और वह न्यायालय जिसके द्वारा उसे दोषी पाया गया है। धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करने से इंकार कर देता है। 4, और उसके विरुद्ध कारावास की कोई भी सजा पारित कर दी। जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। किसी भी बात के बावजूद झूठ बोलना या पसंद किया जाना संहिता या किसी अन्य कानून में निहित है। जिस न्यायालय में अपील की जाती है वह आम तौर पर सजा से संबंधित होती है पूर्व न्यायालय का, या तो स्वयं का हो सकता है प्रस्ताव या दोषी द्वारा किए गए आवेदन पर व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी को बुलाएं और मामले के रिकॉर्ड की जांच करें और ऐसा आदेश पारित करें उस पर जैसा उचित समझे।

(4) x x x x x x

पहला प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय, अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 6 में न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह कहा जाता है कि एस के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता। 11 (3) अधिनियम का प्रावधान केवल उस

मामले तक सीमित है जिसे अपील या संशोधन द्वारा इसकी फाइल में लाया गया है और इसलिए। यह केवल उस अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो विचारण न्यायालय के पास थी, और वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय एस के तहत कोई आदेश नहीं दे सकता था। 6 अधिनियम के अनुसार, जब यह आदेश दिया गया था, तब अधिनियम का विस्तार गुड़गांव जिले तक नहीं किया गया था। इस बारे में संक्षेप में, तर्क आगे बढ़ता है, अधिनियम को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा दिया जाता है, तो यह अधिनियम के लागू होने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके आपराधिक दायित्व को प्रभावित करेगा। इस तर्क के समर्थन में एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की पूर्व सक्रियता के सवाल पर कई निर्णय लिए गए हैं। निहित अधिकारों के संदर्भ में क़ानून का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक कानून जो किसी निहित अधिकार को छीनता है या बाधित करता है, वह पूर्वव्यापी होता है। प्रत्येक पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी है। कला के तहत। 20 संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के किए जाने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उससे अधिक दंड के अधीन

किया जाएगा जो अपराध के किए जाने के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था। लेकिन एक पूर्व कार्योत्तर कानून जो केवल एक आपराधिक कानून की कठोरता को कम करता है, उक्त निषेध के दायरे में नहीं आता है। यदि कोई विशेष कानून इस आशय का प्रावधान करता है, हालांकि संचालन में पूर्वव्यापी, यह मान्य होगा। सवाल यह है कि क्या ऐसा कानून पूर्वव्यापी है और यदि ऐसा है, तो किस हद तक निर्भर करता है । किसी विशेष कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निर्माण के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के लिए । " क़ानून की व्याख्या पर मैक्सवेल", 11वां संस्करण, पीपी. 274-275 , इस प्रकार निर्माण के प्रासंगिक नियम का सारांश दिया गया है ।

" आधुनिक निर्णय की प्रवृत्ति, संपूर्ण है। भौतिक रूप से जो है उसके बीच अंतर को कम करने के लिए एक सख्त और एक लाभकारी निर्माण कहा जाता है। सभी क़ानूनों को अब अधिक ध्यानपूर्वक समझा जाता है। भाषा पर पहरा, और आपराधिक क़ानून के उद्देश्य और इरादे के प्रति अधिक तर्कसंगत संबंध विधायिका, पहले की तुलना में। यह निर्विवाद रूप से सही है कि भेद पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। न्यायिक दिमाग से मिटा दिया गया है, इसके लिए आवश्यक है। हमारे मुक्त संस्थानों की भावना जो व्याख्या है।

सभी विधियों को व्यक्तिगत के अनुकूल होना चाहिए। स्वतंत्रता, और यह प्रवृत्ति अभी भी एक निश्चित रूप से विकसित है। भाषा के दोषों की आपूर्ति करने के लिए अनिच्छा, या द्वारा एक अस्पष्ट मार्ग का अर्थ निकाल दिया। तनावपूर्ण या संदिग्ध प्रभाव. का प्रभाव सख्त निर्माण का नियम लगभग अभिव्यक्त किया जा सकता है। टिप्पणी में कि, एक समान शब्द थे या अस्पष्ट वाक्य का एक उचित संदेह छोड़ देता है। इसका अर्थ जो व्याख्या के कैनन विफल हो जाते हैं हल करना। संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए विषय और विधायिका के खिलाफ जो है खुद को समझाने में असफल रहे। लेकिन यह सर्वोपरि नियम है कि हर क़ानून को समाप्त किया जाना है। इसके व्यक्त या प्रकट इरादे के अनुसार और शरारतों के भीतर सभी मामले हैं, अगर भाषा अनुमति देती है। इसके भीतर गिरने के लिए आयोजित किया जाना है। उपचारात्मक प्रभाव "।

आइए अब हम वर्तमान मामला में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां एक अधिनियम, जो एक नहीं था अधिनियम के समक्ष अपराध को अधिनियम के तहत अपराध बनाया जाता है और न ही क्या यह एक ऐसा मामला है जहाँ अधिनियम के तहत इससे अधिक सजा हो कि अधिनियम से पहले किसी अपराध के लिए

प्राप्त करना अधिरोपित किया जाता है। यह है। एक उदाहरण जहाँ न तो अपराध के तत्व और न ही सजा की सीमाएँ बाधित हैं, लेकिन एक प्रावधान किया गया है- एजेंसी के माध्यम से एक आरोपी के सुधार में मदद करें अदालत। फिर भी कानून पहले किए गए अपराध को प्रभावित करता है।

इसे विचाराधीन क्षेत्र तक विस्तारित किया गया था। इसलिए यह एक पद है वास्तविक कानून और इसका पूर्वव्यापी संचालन होता है। इस पर विचार करते हुए इस तरह के प्रावधान का दायरा हमें लाभकारी नियम को अपनाना चाहिए। न्यायपालिका की आधुनिक प्रवृत्ति द्वारा प्रतिपादित निर्माण संबंधित प्रावधानों के लिए हिंसा किए बिना राय वेंट अनुभाग। अधिनियम की धारा 11 (3), जिसके आधार पर राज्य के विद्वान वकील अपने अधिकांश तर्क को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए, वर्तमान अपील के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं हैः उक्त उप धारा केवल उस मामले में लागू होती है जहां कोई अपील नहीं होती है या पूर्ववर्ती होती है। एक अदालत के आदेश के खिलाफ एक से निपटने के लिए इनकार कर दिया एस के तहत अभियुक्त। 3 या एस। 4 अधिनियम का, और तत्काल मामले में एक अपील सत्र न्यायाधीश के पास रखी गई थी और वास्तव में एक अपील थी। मजिस्ट्रेट के आदेश से वरीयता दी गई। यह प्रावधान कि यह सीधे वर्तमान मामले पर

लागू होता है। 11 (1) अधिनियम, जहाँ अधिनियम के तहत किसी आदेश के तहत कोई भी अदालत बनाई जा सकती है जब मामला आता है तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी अपील या पुनरीक्षण में उसके समक्ष। उप-धारा प्रत्यक्ष रूप से करती है। किसी अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं करता है। अधिनियम के तहत एक आदेश केवल उस मामले में जहां निचली अदालत वह आदेश दिया जा सकता था। इसमें प्रयुक्त वाक्यांश है -

अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय को सक्षम करने के लिए पर्याप्त व्यापक, जब मामला उसके सामने आता है, तो ऐसा आदेश देना। यह था उद्देश्यपूर्ण रूप से व्यापक बनाया गया, जैसा कि अधिनियम बनाया गया था। सामाजिक सुधार की वकालत करें। चूँकि अधिनियम नियम को नहीं बदलता है। वाक्य की मात्रा, लेकिन केवल सुधार के लिए एक प्रावधान का परिचय देता है अपराधी, कोई कारण नहीं है कि विधानमंडल को ऐसा क्यों करना चाहिए। इस तरह की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, भले ही मामला अभियुक्त के खिलाफ किसी न किसी स्तर पर लंबित था न्यायाधिकरणों का पदानुक्रम। यदि एस के प्रावधान। 6 (1) अधिनियम का एस के साथ पढ़ा गया। 11 , हम उसी परिणाम पर पहुँचेंगे। जब एस

11 (1) कहते हैं कि एक अपीलीय अदालत या एक पुनरीक्षण अदालत अधिनियम के तहत आदेश दे सकता है, इसका मतलब है कि यह एक बना सकता है। एस के तहत भी आदेश। 6 (1) अधिनियम से। यदि ऐसा है, तो एस में "कोर्ट"। 6 (1) करेंगे। इसमें एक अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ एक पुनरीक्षण न्यायालय भी शामिल है। यदि एक अपीलीय अदालत या पुनरीक्षण अदालत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराती है, उस धारा के तहत उसे कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। जब तक कि उस धारा में निर्धारित शर्तें पूरी न हो जाएं। क्या यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति "वह न्यायालय जिसके द्वारा प्रति बेटा दोषी पाया जाता है "इसमें अपीलीय या पुनरीक्षण शामिल नहीं है अदालत में जब एक अपीलीय अदालत या एक पुनरीक्षण अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को फर्म करता है या एक ए. सी. को दरकिनार कर देता है उसके द्वारा दिया गया त्यागपत्र और अभियुक्त को दोषी ठहराना, दोनों ही मामलों में यह अभियुक्त को दोषी पाता है, क्योंकि अभियुक्त को दोषी पाए बिना यह या तो दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं कर सकता है या बरी करने के आदेश को दरकिनार करके उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है। यदि राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क, अर्थात्, कि अधिनियम अधिनियम के लागू होने के बाद केवल निचली अदालत द्वारा की

गई दोषसिद्धि पर लागू होगा, स्वीकार किया जाता है, तो इससे कई विसंगतियां पैदा होंगी; इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम किसी दोषसिद्धि पर लागू होगा।

यह अधिनियम लागू होने के बाद एक निचली अदालत द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह एक आरोपी पर लागू नहीं होगा, हालांकि अधिनियम लागू होने के बाद उसकी अपील लंबित थी; यह आरोपी पर लागू होगा यदि अपीलीय अदालत दोषसिद्धि को खारिज कर देती है और मामले को नए सिरे से निपटारे के लिए निचली अदालत में वापस भेज देती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर अपील देर से अदालत ने खुद उसे दोषी ठहराया। दूसरी ओर यदि "दोषी पाए जाने" वाले पूर्व दबाव को स्वाभाविक अर्थ दिया जाता है, तो यह अधिनियम लागू होने के बाद न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम में लंबित आपराधिक कार्यवाही में किसी भी अदालत द्वारा किए गए दोषी के निष्कर्ष को लेगा। इस दृष्टिकोण को रामजी मिसर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है। बिहार राज्य (1)। वर्तमान मामले से संबंधित उस मामले के तथ्य इस प्रकार थेः सहायक सत्र न्यायाधीश आरा ने एक बेसिस्ट को दोषी ठहराया।

एस के तहत। 307 और एस। 326 भारतीय दंड संहिता। चूंकि उक्त धाराओं के तहत अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय थे, इसलिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान बेसिस्ट पर लागू नहीं थे और इसलिए सहायक सत्र न्यायाधीश ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई।

एस के तहत 6 साल के लिए कारावास। 307 भारतीय दंड संहिता और एस के तहत 4 साल के कठोर कारावास के लिए। 326 उक्त संहिता और सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील पर बेसिस्ट को एस के तहत अपराध का दोषी पाया। 324 भारतीय दंड संहिता। यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय एस के तहत आदेश नहीं दे सकता था। 6 (1) द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958, इस आधार पर कि 11 अधिनियम ने उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की। इस तर्क पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" हालाँकि यह संभव है कि एस में शब्द हों। 11 (1[1]) " अधिनियम के तहत आदेश पारित करें" इतनी सख्ती से और शाब्दिक रूप से, लेकिन समझने के लिए इसका अर्थ है "शक्तियों या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना" अधिनियम द्वारा

1(1) [1963] पूरक। 2 एस. सी. और. 745,755

प्रेरित "। यह व्यापक व्याख्या हो सकती है शायद के दायरे और उद्देश्य से उचित ठहराया जाए इस खंड में। धारा 11 को लागू करना है "नहीं समझना" संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी सभी के लिए अदालतें अपराधियों को सजा देने के लिए सशक्त हैं सोनमेंट। इस विश्वविद्यालय के एक लाभकारी प्रावधान को पढ़ने के लिए वर्सल प्रकार एक सीमित अर्थ में, ताकि सीमित किया जा सके के प्रयोग के लिए इन न्यायालयों की शक्ति

एसएस के तहत शक्तियाँ। 3 और 4 अकेले नहीं होगा, हमारे में राय, के ठोस सिद्धांतों के अनुसार हो वैधानिक व्याख्या। इसलिए हम झुके हुए हैं यह अभिनिर्धारित करना कि एस में उल्लिखित न्यायालय। 11 वे हों। विचारण न्यायालय या अपीलीय या पुनरीक्षण का प्रयोग करना इस प्रकार अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सशक्त हैं न केवल एस. एस. के अधीन न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारिता। 3 और 4 और परिणामी प्रावधान लेकिन भी एस के तहत। 6 . "जब यह तर्क दिया गया कि एस में "मई" शब्द है। 11 में से अधिनियम अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय को अपने विकल्प पर शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है और "अधिनियम के तहत कोई भी आदेश" शब्द इसे अधिनियम में निर्धारित

मानकों को स्वीकार किए बिना आदेश देने का अधिकार देता है, यह न्यायालय अस्वीकार करता है। दोनों विवाद। इसने अभिनिर्धारित किया कि "हो सकता है" अभिव्यक्ति का अनिवार्य बल है और अपीलीय न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति उसी प्रकृति और विशेषता की थी और उन्हीं मानदंडों और सीमाओं के अधीन थी जो उन लोगों के समान थीं।

एस. एस. के अधीन न्यायालयों को प्रदान किया गया। 3 और अधिनियम के 4 यह निर्णय तीन प्रस्तावों को निर्धारित करता है, अर्थात्

(i) एक अपील देर से अदालत या एक पुनरीक्षण अदालत एस के तहत एक आदेश दे सकती है। 6 (1) एस के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम का। 11 (1)

(ii) वह पहली बार ऐसा आदेश दे सकता है, भले ही निचली अदालत इस तरह का आदेश नहीं दे सकती थी, उसके द्वारा दिया गया निष्कर्ष; और

(iii) ऐसा आदेश देने में यह एस. एस. में निर्धारित शर्तों के अधीन है। 3 , 4 और अधिनियम के 6 वर्तमान मामले और के बीच एकमात्र अंतर विशेषता उक्त निर्णय यह है कि वर्तमान मामले में निचली अदालत ने किया था आदेश न दें क्योंकि अधिनियम का विस्तार क्षेत्र में नहीं किया गया था। अपने अधिकार क्षेत्र में और उक्त निर्णय में विचारण न्यायालय आदेश नहीं

दिया जैसा कि वह नहीं कर सकता था, इसके निष्कर्ष पर कि अभियुक्त कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी था। जीवन के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने फैसला सुनाया एस के तहत आदेश। 11 अधिनियम की इस तरह की शक्ति स्पष्ट रूप से थी एस द्वारा इसे प्रदान किया गया। 11 अधिनियम से। इसलिए हम मानते हैं कि अपील में अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय, एस के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग। 11 अधिनियम से, बनाएँ एस के तहत एक आदेश। 6 (1) उसके रूप में, अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट से सहमति जताते हुए आरोपी को पाया उन अपराधों का दोषी जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

अगला सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय इसका प्रयोग कर सकता है एस के तहत एक ही शक्ति। 11 (1) अधिनियम से। यह न्यायालय निपटान में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी यह तय करना कि उच्च न्यायालय को संशोधन में क्या निर्णय लेना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का दायरा। यह न्यायालय, इसलिए, या तो एस के तहत ऑर्डर कर सकते हैं। 6 (1) अधिनियम या उच्च न्यायालय को ऐसा करने का निर्देश दें। लेकिन क्या यह न्यायालय

निर्देश देता है ली एस के तहत ऑर्डर करता है। 6 (1) या उच्च न्यायालय को ऐसा करने का निर्देश देता है, वह एस के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। 6 अधिनियम से। एक अदालत 21 वर्ष से कम आयु के प्रति बेटे को कारावास की सजा नहीं दे सकती है जो कारावास से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है (लेकिन आजीवन कारावास के साथ नहीं) जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मामले की प्रकृति भी शामिल है। अपराध और अपराधी का चरित्र, यह नहीं होगा एस के तहत उससे निपटने के लिए वांछनीय। 3 या एस। 4 अधिनियम से। के लिए उक्त कार्रवाई के संबंध में खुद को संतुष्ट करने का उद्देश्य, उप-एस। (2) एस. 6 अधिनियम के अनुसार न्यायालय एक रिपोर्ट मांगेगा परिवीक्षा अधिकारी से और रिपोर्ट पर विचार करें, यदि कोई हो, और चरित्र के संबंध में उसके पास उपलब्ध कोई अन्य जानकारी और अपराधी की शारीरिक और मानसिक स्थिति। कॉन के बाद उक्त सामग्री को दरकिनार करते हुए न्यायालय खुद को संतुष्ट करेगा कि क्या एस के तहत अपराधी के साथ व्यवहार करना वांछनीय है। 3 या एस। 4 में से एक्ट करें। यदि यह संतुष्ट नहीं है कि अपराधी से निपटा जाना चाहिए उक्त दो धाराओं में से किसी एक के तहत, यह सजा पारित कर

सकता है कारण दर्ज करने के बाद अपराधी को कारावास की सजा ऐसा करने के लिए। यह सुझाव दिया जाता है कि अभिव्यक्ति "यदि कोई हो" उप-एस। (2) एस. 6 इंगित करता है कि यह अदालत के लिए कॉल करने के लिए खुला है एक रिपोर्ट या नहीं, लेकिन "होगा" शब्द इसे अनिवार्य बनाता है शर्त और अभिव्यक्ति "यदि कोई हो" केवल संदर्भ में हो सकती है। एक ऐसे मामले को शामिल करता है जहां ऐसी मांग के बावजूद प्रोबा किसी न किसी कारण से राज्य अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। परिवीक्षा कार्यालय से एक रिपोर्ट के लिए कॉल को संक्षेप में बताया के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है। एस. 6 (1) न्यायालय द्वारा अधिनियम। हम सोचते हैं कि परिधि में मामले का रुख सबसे अच्छा तरीका है कि मामले को वापस भेज दिया जाए उच्च न्यायालय एस का पालन करने के बाद आदेश देगा। 6 (1) अधिनियम से।

अंत में यह तर्क दिया जाता है कि हमें इतनी देर नहीं करनी चाहिए कार्यवाही का चरण, और विशेष रूप से अवलोकन को देखते हुए ए. सी. को सजा सुनाने में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय आरोपित, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करें। आम तौर पर यह न्यायालय किसी पक्ष को मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक होगा उससे पहले

पहली बार। लेकिन इस मामले में दोनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अनिवार्य को नजरअंदाज कर दिया अधिनियम के प्रावधान। यह सच है कि आरोपी नहीं लाया था उसके बाद तक न्यायालय के नोटिस के लिए अधिनियम के प्रावधान संशोधन का निपटारा कर दिया गया। लेकिन यह दोषमुक्त नहीं करता है टिप्पणियों को यह नहीं माना जा सकता है कि विद्वान आदी राष्ट्रीय सत्र न्यायाधीश ने खुद को शर्तों से संतुष्ट किया था एस में जैद डाउन। 6 (1) अधिनियम से। इसके अलावा, जैसा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की ओर इशारा किया है

बाहर, वह एस में उल्लिखित मामलों के बारे में कानूनी रूप से खुद को संतुष्ट नहीं कर सकता था। 6 (1) अधिनियम का पालन किए बिना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के ध्यान से भी बच गया उच्च न्यायालय के रूप में और, इसलिए, यह हमारे लिए एक उपयुक्त मामला है कला के तहत टेरफेरेंस। 136 संविधान से। हम अलग कर देते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश और उसे एस के तहत आदेश देने का निर्देश देना। 6 अधिनियम का, या, यदि वह ऐसा चाहता है, तो इसे वापस करने के लिए ऐसा करने के लिए सत्र न्यायालय। हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि हम अभियुक्त के

अपराध के संबंध में अदालतों के निष्कर्ष की शुद्धता पर सवाल उठाने का इरादा नहीं रखते हैं; वास्तव में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उक्त निष्कर्ष पर सवाल नहीं उठाया।

रघुबर दयाल, जे.-मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरी राय है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया है जिसके लिए एस. एस. के प्रावधान हैं। 3 और अपराधी समर्थक अधिनियम, 1958 (अधिनियम सं। 1958 का XX), जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है, लागू हो सकता है, और ऐसा निष्कर्ष, चाहे वह अधिनियम का अनुप्रयोग, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय नहीं कर सकता है एस के तहत कार्रवाई करें। 11 (1) जब मामला आता है तो अधिनियम अपील या पुनरीक्षण में उसके समक्ष। इस मामले में निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था उस क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने से पहले और नहीं कर सका अपीलार्थी को दोषी ठहराने पर सजा देने में उस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखें।

अपीलार्थी को निचली अदालत ने मई में दोषी ठहराया था। मई 31 , 1962 , उस क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने से पहले। यह अधिनियम 1 सितंबर, 1962 को एक सरकारी अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।

अभियोग, जब अपीलार्थी की अपील सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित थी। अपील सितंबर को खारिज कर दी गई थी। सितम्बर 22,1962. अपीलार्थी ने अधिनियम के प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अदालत ने उन पर विचार नहीं किया।

अपीलार्थी पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय गया। 27 सितंबर, 1962 को संशोधन को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया।

28 सितंबर, 1962 को अपीलार्थी ने एक याचिका दायर की एस. एस. के तहत। 3 , 4 और अधिनियम के 6 याचिकाकर्ता होगा रिहा किया गया या कि उसके साथ एस के तहत व्यवहार किया जाए। 562 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे इसके बाद संहिता कहा जाता है। उस ए. पी. दलील को खारिज कर दिया गया था। अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका में न तो इस याचिका का उल्लेख किया गया था और न ही अस्वीकृति के आदेश का। कला के तहत इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इनका संदर्भ पाया जाता है। 134 (1) (ग) 3 अक्टूबर, 1962 के संविधान का, पेज 25 अपील अभिलेख और अपील के आधारों में इसे शामिल किया जाता है। इस

न्यायालय में दायर विशेष अनुमति के लिए याचिका में मुख्य पुनरीक्षण मामले में 27 सितंबर, 1962 के आदेश और फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी, न कि याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ, 1962 का आपराधिक विविध, संख्या 793। विशेष अनुमति याचिका के पैराग्राफ 9 में यह सही बयान नहीं था, इस प्रभाव से कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद के तहत आवेदन दायर किया था। 134 (1) ((c) संविधान के लिए इस न्यायालय में अपील करने के लिए अनुमति के लिए योग्यता प्रमाण पत्र का अनुदान, लेकिन इसे 19 अक्टूबर, 1962 को अस्वीकार कर दिया गया था। जमीन, रिकॉर्ड के रूप में एड, प्रथम दृष्टया दिखाया कि ऐसा आवेदन आपराधिक संशोधन, संख्या 1172 में आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए था। 1962 का। इन परिस्थितियों में, दी गई विशेष छुट्टी है - निरस्त किया जा सकता है।

अपीलीय न्यायालय यह देखता है कि अभिलेख पर सामग्री पर नीचे दिए गए न्यायालय का आदेश सही है या नहीं और उसे एक आदेश पारित करना होगा। उस सामग्री पर सही आदेश। यदि निचली अदालत उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती थी जो उस समय लागू नहीं था जब उसने आरोपी को दोषी पाया था, तो अपील अदालत उन

प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती थी जब तक कि अधिनियम विशेष रूप से उन प्रावधानों के लिए प्रावधान नहीं करता। जिन मामलों में ऐसा हुआ था उन पर लागू होगा। इसके आवेदन से पहले निर्णय लिया गया था। अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और मुझे उस संबंध में अधिनियम के अनुकूल दृष्टिकोण से कोई आवश्यक निहितार्थ नहीं मिलता है।

यह सच है कि अपीलीय न्यायालयों ने पक्षकारों को मामले के लंबित रहने के दौरान अधिनियमित कानून का लाभ उठाने की अनुमति दी है। लेकिन यह तब किया जाता है जब पक्षकार परिवर्तित कानून को देखते हुए आगे मुकदमा कर सकते हैं और कार्यवाही की बहुलता को बचाने के लिए किया जाता है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

आम तौर पर, एक मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए गए मामले के लिए कुछ साल लगते हैं, जो पहली बार में इसका परीक्षण करता है, और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन में अंतिम आदेश पारित करने में कुछ साल लगते हैं। आम तौर पर, मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के पास अपील की जाती है और सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जाता है। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के समक्ष दो कार्यवाहियों में समय लगता है। यह अधिनियम एक अखिल

भारतीय अधिनियम है और अधिनियम के प्रवर्तन से पहले निचली अदालतों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाएगा। यह मानना बहुत अधिक है कि विधायिका का इरादा था कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि के ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के सभी आदेश स्वचालित रूप से अवैध हो जाते हैं और अपील और संशोधन के न्यायालयों द्वारा सुधार के लिए उत्तरदायी होते हैं। न केवल उन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए था, बल्कि सजा के बारे में मजिस्ट्रेट के आदेशों को दरकिनार करने से मामले समाप्त नहीं होते, बल्कि मजिस्ट्रेट या अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आगे की कार्यवाही की जाती कि क्या एस. एस. के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। एक्ट करें। उन सभी असंख्य मामलों को फिर से खोलना होगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि विधायिका ने इस तरह के परिणाम का इरादा किया होगा और अगर उसने वास्तव में ऐसा इरादा किया होता तो खुद को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता।

अधिनियम की धारा 3 न्यायालय को चेतावनी और धाराओं के बाद दोषियों को रिहा करने का अधिकार देती है। 4 न्यायालय को अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने का अधिकार देता है। वह

न्यायालय जिसे इन धाराओं के तहत कार्रवाई करनी है, वह न्यायालय है जिसके द्वारा व्यक्ति को दंडात्मक धाराओं में और निर्दिष्ट धाराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों में अपराधों का दोषी पाया जाता है। इस तरह के आदेश किसी भी सजा के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सजा देने के बजाय दिए जाते हैं जो उसे दी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि इन धाराओं के तहत कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी पाता है।पहली बार एक व्यक्ति को रेस का दोषी पाया जा सकता है। विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा दंडात्मक अपराध यदि वह एक ऐसे अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि को बदल देता है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। उन धाराओं में से किसी एक के लिए जो उनमें से किसी के अंतर्गत आती है, या उच्च न्यायालय द्वारा यदि वह अभियुक्त व्यक्ति को दोषी पाता है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील। इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी पाया है। पुनरीक्षण का न्यायालय दोषमुक्त किए जाने के निष्कर्ष को दोषमुक्त किए जाने के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसा कोई मामला उत्पन्न नहीं हो सकता है जिसमें पहली बार पुनरीक्षण न्यायालय किसी

अभियुक्त को किसी अपराध का दोषी पाए। जिसके लिए एस. एस. के प्रावधान हैं। 3 और अधिनियम के 4 लागू होते हैं।

जब एक अपीलीय न्यायालय एक की दोषसिद्धि की पुष्टि करता है। व्यक्ति यह न्यायालय नहीं है जो उसे दोषी पाता है लेकिन वह है न्यायालय जो विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करता है एक राय बनाने पर व्यक्ति का दोषी होना कि आदेश ट्रायल कोर्ट सही है। यदि 'वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यक्ति दोषी पाया जाता है' अभिव्यक्ति में अपीलीय न्यायालय को शामिल किया जाना था। अपराध के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि की पुष्टि करना जो दोनों धाराओं में से किसी के तहत आने पर, अपीलीय न्यायालय को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती इन धाराओं के तहत, उप-धाराओं के रूप में। (1) एस. 11 करता है। यह उप खंड में लिखा हैः

" संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो अपराधी पर मुकदमा चलाने और उसे कारावास की सजा देने के लिए सशक्त है और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी जब मामला अपील पर या पुनर्विचार में उसके समक्ष आता है। "

इस उप-धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि जिस न्यायालय को अधिनियम के तहत आदेश देने का अधिकार है, पहला उदाहरण वह न्यायालय है जो प्रयास करने का अधिकार रखता है और अपराधी को कारावास की सजा, यानी मूल परीक्षण अदालत। इसे अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। अधिनियम के तहत आदेश उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी किए जा सकते हैं जब मामला अपील पर उसके सामने आता है या पुनरीक्षण में। सवाल यह है कि किस मामले में उच्च न्यायालय एस या कोई अन्य न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह इसका प्रयोग तब कर सकता है जब वह मामला जिसमें निचली अदालत शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, उसके सामने आता है। इसका निष्कर्ष 'भी' शब्द के उपयोग से निकाला जाना चाहिए और उस अवसर से जब उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है, यह तब होता है जब मामला अपील या संशोधन पर उसके समक्ष आता है। तत्पश्चात, ऐसा मामला होना चाहिए जिसमें विचारण न्यायालय एक निश्चित कार्रवाई कर सके जिसमें उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय भी कर सके। कार्रवाई तभी करें जब वह अपील पर या पुनरीक्षण में उसके समक्ष आए सायन। मैं भाषा का अर्थ लगाना उचित नहीं समझता।

उप-से। (1) इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय उसके समक्ष अपील या पुनरीक्षण के सभी मामलों में कार्रवाई कर सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि क्या निचली अदालत कर सकती थी। उन मामलों में अधिनियम के तहत एक आदेश या नहीं।

एस की योजना। 11 ऐसा लगता है कि यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उप-धारा (1) उन न्यायालयों का उल्लेख करती है जो अधिनियम के तहत आदेश दे सकते हैं। उप-धारा (2) एक अपील प्रदान करती है जहाँ एस के तहत एक आदेश दिया जाता है। 3 या एस। 4 किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी पर मुकदमा चलाने में किया जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई अदालत किसी अपराधी के दोषियों पर मुकदमा चलाती है। उसे और एस के तहत कार्रवाई करता है। 3 या एस। 4 , उस मामले में एक अपील होगी। बेशक अपीलीय अदालत के लेने का कोई सवाल ही नहीं है। एस के तहत कार्रवाई। 3 या एस। 4 ऐसी अपीलों में उत्पन्न होता है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और अपीलीय न्यायालय केवल दोषसिद्धि की शुद्धता पर ध्यान देगा और यदि वह एस के तहत कार्रवाई पाता है। 3 या एस। 4 अनुचित होने के लिए, उस आदेश को दरकिनार भी कर सकते हैं और उप-धाराओं में दिए गए उपयुक्त

वाक्य पारित कर सकते हैं। (4) उप-धारा (2) अपील और उप-धाराओं के लिए प्रावधान करती है। (4) एस. एस. के तहत किए गए किसी भी आदेश के औचित्य पर विचार करने के लिए अपीलीय न्यायालय के लिए प्रावधान करता है। 3 या अधिनियम के 4. उपबंधों में ये प्रावधान। (2) और उप-एस। (4) उन मामलों को समाप्त करें जिनमें एस. एस. के तहत आदेश दिए जाते हैं। 3 या 4 हो सकता है उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया।

जबकि एसएस। 3 और 4 उन धाराओं के तहत आदेश देने के लिए न्यायालय में एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।जटिलताएँ, उप-सं। (1) एस. 6 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अपराधों का दोषी ठहराना न्यायालय के लिए अनिवार्य बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सजा न देने के लिए कारावास से दंडनीय कारावास के लिए इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जब तक कि यह संतुष्ट न हो उप-धारा में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि एस के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा। 3 या एस. 4 और उस मामले में उसे कारावास की सजा सुनाने के अपने कारणों को दर्ज करना होगा। उप-धारा (2) न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है और खुद को

संतुष्ट करने के लिए इसे साइड करें कि क्या यह वांछनीय नहीं होगा। एस के तहत सौदा करने में सक्षम। 3 या एस। 4. एस के ये प्रावधान। एस के तहत कार्रवाई करने के लिए विचारण न्यायालय का विवेकाधिकार। 3 और एस। 4 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के संबंध में और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। हालाँकि, एक अदालत ऐसे व्यक्ति को विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद ही कारावास की सजा दे सकती है। और अंत में खुद को संतुष्ट करते हुए कि एस के तहत आदेश देना वांछनीय नहीं होगा। 3 या एस। 4 उस व्यक्ति के बारे में।

एक मामला जिसके लिए एस के प्रावधान हैं। 6 आवेदन को निपटाया जाता है उप-एस द्वारा। (3) एस. 11 जिसमें यह प्रावधान है कि जब किसी न्यायालय ने एस के तहत व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से इनकार कर दिया है। 3 या एस। 4 और कारावास की सजा पारित की है और जब कोई अपील नहीं की गई है या उस आदेश से कोई भी अपील नहीं की गई है, तो वह न्यायालय, जिसके लिए आम तौर पर अदालत की सजा से अपील की जाती है, स्वतः संज्ञान ले सकता है या दोषी व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, मामले के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर

सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। बेशक, यदि आदेश अपील योग्य है, तो अपीलीय न्यायालय के तहत प्रदत्त शक्ति को देखते हुए मामले पर विचार कर सकता है। उप-एस। (1) , जो अपीलीय न्यायालय को अधिनियम के तहत कोई आदेश देने में सक्षम बनाता है जब मामला उसके समक्ष आता है। कार्रवाई उप-ओं के अंतर्गत। (3) , यह स्पष्ट है, अपीलीय द्वारा लिया जा सकता है। न्यायालय केवल उन मामलों में जिनमें विचारण न्यायालय ने एस के तहत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। 3 या एस। 4 , अर्थात्, विचारण न्यायालय ने, किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि और सजा सुनाने के समय, एस के तहत आदेश देने की शक्ति। 3 या एस। 4 और यह महसूस किया कि इस तरह का आदेश वांछनीय नहीं था। यदि उस समय उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और उसने एक गैर-अपील योग्य आदेश पारित किया है, या जब दोषी व्यक्ति अपील नहीं करता है, तो उप-धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। (3) क्योंकि यह किसी भी औचित्य के साथ नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। एस के तहत। 3 या एस। 4. यह इस तथ्य का एक मजबूत संकेत है कि उच्च न्यायालय या किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय को एस के तहत

प्रदत्त शक्तियांः 11 उनके समक्ष आने वाले मामलों में प्रयोग किया जाना है जिसमें विचारण न्यायालय स्वयं अधिनियम के तहत आदेश दे सकता था।

किसी आनुषंगिक मामले का भी उल्लेख किया जा सकता है। अ. एस के तहत चेतावनी का आदेश। 3 मामले को समाप्त कर देता है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम आदेश होने के नाते, निश्चित रूप से अपीलीय न्यायालय के आदेशों के अधीन, यदि दोषी व्यक्ति अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करता है। एस के तहत किसी आदेश के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 4 , एक आदेश जो निर्देश देगा कि दोषी व्यक्ति को उसके प्रवेश पर रिहा कर दिया जाए। न्यायालय के रूप में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए बांड में शामिल होना। इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दे सकते हैं। अपराध के लिए दी गई सजा को स्थगित कर दिया जाता है और दोषी व्यक्ति को भविष्य में उसके खिलाफ उचित सजा दिए जाने का खतरा रहता है। कुछ परिस्थितियाँ। धारा 9 में अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विजेता की विफलता के मामले में प्रावधान है कि वह और उसके प्रतिभूओं को अदालत में तलब किया जाए जो रिमांड कर सकता है अभियुक्त को अभिरक्षा देने या उसे जमानत देने के लिए और यदि वह संतुष्ट है कि वह

बंधपत्र की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है,मूल अपराध के लिए उसे तुरंत सजा देना और जहां पहली बार उस पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने में विफलता है। 50 / - बंधन के बल में निरंतरता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। यदि कोई दोषी व्यक्ति बांड की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे एक तरह से सजा के अलावा पहली बार में मिलने वाली सजा से अधिक बड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। जो उस पर पारित किया जाएगा वह पहले से ही था, एक निश्चित के लिए इस अवधि में, बंधन की शर्तों का पालन किया गया था और यह भी था, अपराध का शिकार और कार्यवाही की लागत जो हैं - ठीक हो गया। कोड भुगतान के लिए प्रदान नहीं करता है लागत और मुआवजे के भुगतान के लिए प्रावधान जब एक अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने से बाहर का आदेश दिया; एस. एस. के माध्यम से। 545 और संहिता का 546ए।

इस न्यायालय ने रामजी मिसर बनाम में अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर विचार किया। बिहार राज्य (') और अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त धाराओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि। , एसएस। 3 , 4 और एक अभियुक्त के मामले में अधिनियम की धारा 6, जिसके अपराधों के विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, जिन पर वे धाराएं लागू नहीं होती हैं, को

अपीलीय न्यायालय द्वारा एक ऐसे अपराध में परिवर्तित कर दिया गया था, जिस पर उन धाराओं के प्रावधान लागू होते हैं, तर्क के आधार पर धारा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस सिद्धांत पर कि एक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही आदेश था जिसे निचली अदालत को पारित करना चाहिए था, निचली अदालत के निर्णय की तारीख होगी। यह उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो मैंने ऊपर व्यक्त किया है। यह माना जा सकता है कि उस मामले में विचारण न्यायालय एस के तहत आदेश दे सकता है। 4 अधिनियम के उस समय के प्रावधानों के अनुसार, यदि उस ने उस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया था, जिसके लिए एस के प्रावधान हैं, तो उस समय वह एक बेसिस्ट को दोषी ठहराता है, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम थी। 4 आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को इस तरह के अपराध में बदल दिया लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि वह एस के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था। 6 अधिनियम से। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह हो सकता है। तत्काल मामले में, निचली अदालत इस साधारण कारण से अधिनियम के पी. और. सी. दृष्टिकोण के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं कर सकी कि जिस दिन उसने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था, उस दिन अधिनियम लागू नहीं था।

इसलिए, मेरी राय है कि हमारे सामने निर्णय का बिंदु है। अर्थात्, क्या अपीलीय न्यायालय उन मामलों में अधिनियम के तहत आदेश दे सकता है जिनमें निचली अदालत दोषसिद्धि की तारीख पर अधिनियम के तहत आदेश नहीं दे सकती थी, उस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। यह सवाल इस सवाल से बहुत अलग है कि क्या कोई अपीलीय अदालत अधिनियम के तहत आदेश दे सकती है जब वह अपीलकर्ता की सजा को उस अपराध में बदल देती है जिसके संबंध में अधिनियम के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश दिया जा सकता था। रामी के मामले में(')।

इसलिए मेरी राय है कि उच्च न्यायालय इस मामले में अधिनियम के तहत कोई आदेश नहीं दे सकता था और इसलिए यह अपील विफल होनी चाहिए। मैं तदनुसार इसे खारिज कर दूंगा।

<u>आदेश</u>

बहुमत की राय के अनुसार, हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और उसे धारा के तहत आदेश देने का निर्देश देते हैं। परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 की धारा 6, या, यदि वह चाहे, तो ऐसा करने के लिए उसे सत्र न्यायालय में भेज सकती है।

अपील की अनुमति दी गई।

नोटः- यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सीमा हुड्डा** (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।